उत्तर की चीनी मिलें खस्ताहाल

स्टॉक से ज्यादा गन्ना बकाया और कर्ज भुगतान बढ़ा सकती है परेशानी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 1 जुलाई

भारत के उत्तरी क्षेत्र खासतौर पर उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर बैंक का कर्ज उनके पास सुरक्षित स्टॉक से कहीं ज्यादा है। इससे पता चलता है कि अपना सारा स्टॉक बेचने के बाद भी ये मिलें अपना कर्ज चुकता नहीं कर पाएंगी जिसकी वजह से अगले सीजन के लिए कार्यशील पूंजी का इंतजाम करने की उनकी क्षमता पर बुरा असर पड़ने का खतरा मंडरा रहा है।

मार्च, 2014 में खत्म हुई तिमाही में बजाज हिंदुस्तान (बीएचएल) के खातों में 5,585.71 करोड़ रुपये (लघु और दीर्घावधि) के ऋण दर्ज हैं जबकि कुल स्टॉक महज 2,673.50 करोड़ रुपये का है। खास बात यह है कि भारत के सबसे बड़े चीनी निर्माता बीएचएल को 23 मई तक 1,937.10 करोड़ रुपये का गन्ने का बकाया भुगतान करना है। लघु अवधि के ऋण और गन्ने का बकाया भुगतान को मिलाकर कंपनी की देनदारी 5,013.2 करोड़ रुपये बनती है जो कंपनी के पास 23 मई तक के स्टॉक के मुकाबले 53 फीसदी अधिक है।

चूंकि चीनी मिलें सरकार से मिलने वाली रियायतें हासिल करने के लिए किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान करने का वादा करते हुए एक हलफनामा सरकार को सौंपने को तैयार हो गई हैं, सरकार चीनी मिलों को राहत देने के लिए एक पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। एसवीएस सिक्योरिटीज के रणनीतिकार हरीश वासुदेवन कहते हैं, 'उत्पादन और निर्यात पर मिलने वाली रियायतों के साथ ही आयात पर लगे प्रतिबंध के चलते घरेलू बाजार में चीनी की कीमत बढ़ने की आशंका है और इसका असर चीनी मिलों पर भी पड़ेगा। बजट के बाद बाजार में कुछ सुधार हो सकता है।'

ऐसा ही हाल सिंभावली शुगर्स, मवाना शुगर्स और राणा शुगर्स का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सरकार ने हाल ही में चीनी मिलों के लिए कुछ कदम उठाए हैं। आयात शुल्क को मौजूदा 15 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने के अलावा उत्पाद शुल्क के बराबर ऋण की समयसीमा को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया। इन कदमों के चलते चीनी की कीमत में प्रति किग्रा 2 रुपये का इजाफा हुआ जिसकी वजह से चीनी मिलों के मुनाफे में इजाफा हो रहा है। उद्योग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'मिलों ने बढ़ती कीमतों के मद्देनजर चीनी का स्टॉक रखा था।

फरवरी से सरकार की ओर मिलने वाले मदद की उम्मीद के बीच खुले बाजार में चीनी की बिक्री मंद पड़ गई थी।' दरअसल रंगराजन समिति ने चीनी मिलों को मुनाफे का करीब 70 फीसदी किसानों को देने का सुझाव दिया था, उत्तर भारत की चीनी मिलें भुगतान नहीं कर सकीं।

कर्ज अदायगी की समस्या से जूझ रही हैं उत्तर भारत की चीनी मिलें।

Business Standard
2/7/14